विचार बिन्दु

जब जिन्दगी को अपने दिल के गीत सुनाने का मौका नहीं मिलता, तब वह अपने मन के विचार सुनाने के लिए दार्शनिक पैदा कर देती है।

–खलील जिब्रान

स्वदेशी माइक्रोचिप: आत्मनिर्भरता की ओर ऐतिहासिक कदम

भारत ने अपनी पहली स्वदेशी चिप बना लेने की घोषणा की है। इसका नाम भारतीय वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के नाम पर विक्रम दिया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी को इसरो द्वारा विकसित 'विक्रम 32-बिट प्रोसेसर' भेंट किया। इसरो की सेमीकंडक्टर लैब में निर्मित यह चिप, अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान की चरम स्थितियों में उपयोग के लिए तैयार किया गया यह पहला पूर्णत: भारत में निर्मित प्रोसेसर है। विक्रम चिप को इस हिसाब से बनाया गया है कि वह अत्यधिक तापमान और अंतरिक्ष की विषम परिस्थितियों का सामना कर सके। यह चिप पर्याप्त मात्रा में मेमोरी को संभाल सकती है और रॉकेटों की लॉन्चिंग के लिए जरूरी जटिल निर्देशों का पालन कर सकती है। इन खूबियों की वजह से इस चिप को रक्षा, विमानन, ऑटोमोटिव और ऊर्जा जैसे जरूरी क्षेत्रों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वैश्विक स्तर पर सेमीकंडक्टर बाजार अब 600 अरब डॉलर का हो चुका है और आने वाले सालों में इसके एक हजार अरब डॉलर से अधिक का हो जाने की उम्मीद है। सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भारत के आगे बढ़ने की गति को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि भारत इस एक हजार अरब डॉलर के बाजार में अहम् हिस्सेदारी हासिल कर सकेगा। इस दिशा में 'सेमीकॉन' कार्यक्रम साल 2021 में शुरू किया गया था। 2023 में देश के पहले सेमीकंडक्टर प्लांट को स्वीकृति दी गई। 2024 में कई और प्लांटों को स्वीकृति मिली और 2025 में पांच अन्य परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई। इस समय फिलहाल दस सेमीकंडक्टर परियोजनाएं चल रही हैं, जिनमें 18 अरब डॉलर यानी 1.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश हो चुका है। नोएडा और बेंगलुरु में विकसित किए जा रहे डिजाइन सेंटरों में दुनिया की कुछ सबसे आधुनिक चिपों पर काम हो रहा है जिनमें प्रत्येक चिप में अरबों ट्रांजिस्टर समा सकते हैं। सीजी पावर कंपनी के पायलट प्लांट में इस साल अगस्त में काम शुरू हो चुका है और एक अन्य पायलट प्लांट में काम जल्द ही शुरू होने वाला है। इसके अलावा, टाटा और माइक्रोन के टेस्ट चिपों का पहले से ही उत्पादन हो रहा है। अनुमान है कि इस साल के अंत तक भारत में चिपों का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो जाएगा। सेमीकंडक्टर चिपों का उत्पादन शुरू करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (आईएसएम) शुरू किया था। इसके लिए सरकार ने 76 हजार करोड़ रुपये की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना शुरू की थीजिसके तहत, स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स की मदद करने के लिए 23 चिप डिजाइन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।

माइक्रोचिप एक बहुत ही छोटी इलेक्ट्रॉनिक चिप होती है, जिसे इंटीठोटेड सर्किट (आईसी) भी कहते हैं। इसमें हजारों, लाखों या अरबों ट्रांजिस्टर, रेसिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक घटक एक ही सिलिकॉन के टुकड़े पर बनाए जाते हैं। आसान भाषा में कहें तो माइक्रोचिप एक छोटा-सा दिमाग है जो किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को सोचने-समझने और काम करने की क्षमता देता है। यह ज्यादातर सिलिकॉन से बनाई जाती है और वह आकार में बहुत ही छोटी (कुछ मिलीमीटर की) होती है, लेकिन इसकी क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। इसका काम डेटा को प्रोसेस करना, स्टोर करना और निर्देशों के हिसाब से काम करना। इसका उपयोग कंप्यूटर, मोबाइल, टीवी, कार, एटीएम कार्ड, स्मार्टफोन, रोबोट, मेडिकल उपकरण, यहां तक कि पालतू जानवरों की पहचान के लिए भी किया जाता है। माइक्रोप्रोसेसर एक तरह से कंप्यूटर/मोबाइल का दिमाग होता है। इसी प्रकार माइक्रोकंट्रोलर वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव जैसे उपकरणों को भी नियंत्रित करता है। मेमोरी चिप डेटा को स्टोर करती है।

वर्तमान में दुनिया में अगर तेल को ऊर्जा का ईंधन माना जाए तो माइक्रोचिप को आधुनिक तकनीक का वाहक कहा जा सकता है। मोबाइल फोन, कंप्यूटर, इंटरनेट, अंतरिक्षयान, चिकित्सा उपकरण, बैंकिंग व्यवस्था, स्मार्ट कारें और कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकहर जगह माइक्रोचिप निर्णायक भूमिका निभाती है। डिजिटल युग में इसकी अहमियत इतनी गहरी है कि बिना माइक्रोचिप के आधुनिक जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। इस पृष्ठभूमि में भारत द्वारा अपनी पहली स्वदेशी माइक्रोचिप 'विक्रम' का निर्माण केवल तकनीकी उपलब्धि नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता, राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक संप्रभुता की दिशा में क्रांतिकारी पहल है। 21वीं सदी में जो भी तकनीकी क्रांति हम देख रहे हैं, जैसे 5जी, क्वांटम कंप्यूटिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एएआई), इंटरनेट ऑफ थिंग्स या स्वचालित वाहन-उन सबका केंद्र माइक्रोचिप ही है। विश्व स्तर पर अमेरिका, ताइवान, दक्षिण कोरिया और जापान इस क्षेत्र में अग्रणी रहे हैं। ताइवान की कंपनी टीएसएमसी और दक्षिण कोरिया की सैमसंग इसकी शीर्ष निर्माता कंपनियां हैं। अमेरिका डिज़ाइन और अनुसंधान में अग्रणी है, जबकि चीन बड़े पैमाने पर उत्पादन पर ध्यान दे रहा है। इस तरह से माइक्रोचिप एक सामरिक तकनीक भी है। यही कारण है कि अमेरिका और चीन के बीच तकनीकी शीतयुद्ध का सबसे बड़ा केंद्र सेमीकंडक्टर उद्योग है।

'विक्रम' की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसका पूरी तरह स्वदेशी डिज़ाइन है। स्वदेशी डिज़ाइन होने से साइबर सुरक्षा और डेटा संरक्षण में भी यह मददगार है। कह सकते हैं कि आत्मनिर्भर भारत का यह स्तंभ है। यह भारत को आयात-निर्भरता से मुक्त करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। इससे रक्षा उपकरणों और संवेदनशील क्षेत्रों में विदेशी चिप्स पर निर्भरता खत्म होगी जिससे अरबों डॉलर का विदेशी मुद्रा व्यय बचेगा और देश में निवेश बढ़ेगा। स्वदेशी चिप होने से भारतीय स्टार्टअप और उद्योग नए प्रयोग कर पाएंगे और सेमीकंडक्टर विनिर्माण उद्योग से लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा।

सूचना प्रौद्योगिकी और सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भारत विश्व में अग्रणी रहा है, लेकिन हार्डवेयर निर्माण, खासकर सेमीकंडक्टर में, पिछड़ा हुआ था। भारत की विशाल जनसंख्या और डिजिटल क्रांति के बावजूद अब हम विदेशी माइक्रोचिप पर निर्भर रहे हैं। चाहे वह मोबाइल फोन हो या लैपटॉप, रक्षा उपकरण हो या मेडिकल मशीनरी-सब में आयातित चिप्स का उपयोग होता है। इस निर्भरता की कई समस्याएं रही हैं। हर साल अरबों डॉलर का विदेशी मुद्रा खर्च होती है। रक्षा और संचार क्षेत्र में विदेशी चिप पर निर्भरता जोखिम भरी भी मानी जाती है। भारत में अपनी चिप बनाने के लिए नवाचार की क्षमता लंबे समय तक सीमित रही। इससे आपूर्ति श्रृंखला का संकट भी रहा। कोविड महामारी के दौरान वैश्विक चिप संकट ने भारत सहित पूरी दुनिया को हिला दिया था। यही कारण था कि भारत सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत की और आत्मनिर्भर भारत अभियान में सेमीकंडक्टर को शीर्ष प्राथमिकता दी। इसी कड़ी में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) मद्रास के शक्ति माइक्रोप्रोसेसर प्रोजेक्ट से जुड़े वैज्ञानिकों ने भारत की पहली स्वदेशी माइक्रोचिप 'विक्रम' का विकास किया है। यह उपलब्धि केवल एक तकनीकी परियोजना नहीं बल्कि भारतीय आत्मनिर्भरता की दिशा में मील का पत्थर है। 'विक्रम' चिप का नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉ. विक्रम साराभाई के सम्मान में उचित ही रखा गया है। 'विक्रम' की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसका पूरी तरह स्वदेशी डिज़ाइन है। विक्रम को भारतीय शोधकर्ताओं ने डिज़ाइन करके विकसित किया है। यह ओपन-सोर्स आर्किटेक्चर है जो आरआईएससी-वी पर आधारित है, जिससे भविष्य में उस पर स्वतंत्र रूप से विकास संभव है जो इसे वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाएगा। यह किफायती और ऊर्जा दक्ष है अर्थात विक्रम चिप कम ऊर्जा खपत और उच्च प्रदर्शन के साथ कार्य कर सकती है। इसी कारण इसे रक्षा, संचार, शिक्षा, ऑटोमोबाइल और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स तक में उपयोग किया जा सकता है। स्वदेशी डिज़ाइन होने से साइबर सुरक्षा और डेटा संरक्षण में भी यह मददगार है। कह सकते हैं कि आत्मनिर्भर भारत का यह स्तंभ है। यह भारत को आयात-निर्भरता से मुक्त करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। इससे रक्षा उपकरणों और संवेदनशील क्षेत्रों में विदेशी चिप्स पर निर्भरता खत्म होगी जिससे अरबों डॉलर का विदेशी मुद्रा व्यय बचेगा और देश में निवेश बढ़ेगा। स्वदेशी चिप होने से भारतीय स्टार्टअप और उद्योग नए प्रयोग कर पाएंगे और सेमीकंडक्टर विनिर्माण उद्योग से लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा।

वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखें तो विश्व में सेमीकंडक्टर की मांग लगातार बढ़ रही है। अनुमान है कि 2030 तक यह बाज़ार एक ट्रिलियन डॉलर से भी अधिक का हो जाएगा। भारत इस विशाल अवसर का लाभ उठा सकता है क्योंकि भारत के पास पहले से ही मजबूत आईटी सेक्टर है, प्रचुर मानव संसाधन है, बड़ी घरेलू मांग है और साथ में सरकारी प्रोत्साहन योजनाएं मौजूद हैं। 'विक्रम' चिप का निर्माण भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बना सकता है। मगर इस राह में चुनौतियां भी कम नहीं है। यहां निर्माण अवसंरचना की कमी है। भारत में बड़े पैमाने पर चिप फैब्रिकेशन यूनिट अभी नहीं हैं। सेमीकंडक्टर उद्योग पूंजी-सघनता वाला उद्योग है। इसमें अरबों डॉलर की आवश्यकता होगी। अमेरिका, चीन, ताइवान और कोरिया इस क्षेत्र में पहले से बहुत आगे हैं। इस अकेले उद्योग के लिए लाखों कुशल इंजीनियरों और तकनीशियनों की भी ज़रूरत होगी। साथ ही वैश्विक राजनीतिक दबाव को भी झेलना होगा क्योंकि सेमीकंडक्टर उद्योग पर भूराजनीतिक खींचतान का असर भारत पर भी पड़ सकता है। भारत को 'विक्रम' जैसी परियोजनाओं को केवल प्रतीकात्मक उपलब्धि न मानकर इसे बड़े पैमाने पर उद्योग में बदलना होगा। इसके लिए सरकार को लंबी अवधि की नीति और वित्तीय सहायता जारी रखनी होगी। साथ ही निजी क्षेत्र और स्टार्टअप को शोध और नवाचार के लिए प्रोत्साहित करना होगा और देश के विश्वविद्यालयों और संस्थानों को सेमीकंडक्टर शिक्षा और प्रशिक्षण पर ध्यान देना होगा। 'विक्रम' केवल एक माइक्रोचिप नहीं, बल्कि भारत की तकनीकी स्वतंत्रता का प्रतीक है। यह भारत को उपभोक्ता से निर्माता और नवोन्मेषक में बदलने का अवसर देता है। जिस तरह 20वीं सदी में अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा ने राष्ट्रों की ताकत तय की थी, उसी तरह 21वीं सदी में माइक्रोचिप और सेमीकंडक्टर तकनीक यह भूमिका निभाएंगे। भारत का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि हम इस अवसर को किस हद तक रणनीतिक दृष्टि से संभालते हैं। अगर 'विक्रम' को उद्योग, शिक्षा और नीतिगत स्तर पर व्यापक सहयोग मिले तो यह न केवल भारत की तकनीकी दिशा बदलेगा बल्कि विश्व मंच पर भारत को अग्रणी स्थान दिला सकता है।

–अतिथि संपादक,
राजेन्द्र बोड़ा
(वरिष्ठ पत्रकार एवं विश्लेषक)

भारतीय भाषा-भावों का संरक्षक "राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ"

डॉ. निमिषा गौड़

भाषा मनुष्य के विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने का सबसे सुंदर माध्यम है। यही वह साधन है जो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है। भाषा के माध्यम से ही व्यक्ति अपने परिवार, समाज और राष्ट्र से जुड़ता है। और यही जुड़ाव पूरी दुनिया के देशों को एक भावनात्मक सूत्र में बांध देता है। किसी भी क्षेत्र की भाषा, वहां की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परंपराओं का सजीव प्रतिबिंब होती है। यह हमारी विरासत की अभिव्यक्ति करती है और जनमानस को अपनी जड़ों से जोड़ती है। भाषा के माध्यम से विचार प्रकट होते हैं और यही जुड़ाव राष्ट्र की पहचान बन जाता है। यही पहचान राष्ट्र के विकास की आधारशिला होती है। भारत वासियों की भाषा और विचार, हमारी सनातन संस्कृति और सभ्यता की अमूल्य देन हैं। भारतीयों की राष्ट्रीय एकात्मता हमारी सांस्कृतिक धरा के साथ अनादिकाल से प्रवाहित होती आ रही है। इस सांस्कृतिक प्रवाह में संस्कृत को सभी भारतीय भाषाओं की जननी माना गया है। समय के साथ भारत में अनेक भाषाओं का उद्भव हुआ- जैसे हिन्दी, बंगला, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओड़िया और असमिया आदि। इन्हीं भाषाओं की समृद्ध परंपरा में हिन्दी ने एक ऐसी कड़ी के रूप में स्थान प्राप्त किया है, जिसने उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक पूरे देश को संवाद के सूत्र में बांधा।

हिंदी नवजागरण के अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है–

निज भाषा उन्नति अहै,
सब उन्नति को मूल।
बिना निज भाषा ज्ञान के,
मिटै न हीय को शूल।।

उक्त प्रचलित पंक्तियों के भावों में अपनी मातृ भाषा के विकास से सभी प्रकार की उन्नति का मूल आधार है। अपनी भाषा के ज्ञान के बिना ह्रदय की पीड़ा को दूर नहीं किया जा सकता है।

भारत में विदेशी आक्रांताओं ने न केवल हमारी भूमि पर अधिकार जमाने का प्रयास किया, बल्कि हमारी संस्कृति, भाषा और सामाजिक एकता पर भी चोट की। मुग़ल, अफ़ग़ान और अंग्रेजों के शासनकाल में भाषाओं को कभी सांस्कृतिक नियंत्रण का माध्यम बनाया गया तो कभी प्रशासनिक कामकाज में उनकी सीमाएँ तय की गईं। अंग्रेजों ने खास तौर पर "फूट डालो, राज करो" की नीति अपनाई। उन्होंने उत्तर और दक्षिण, हिंदी और द्रविड़ भाषाओं के बीच मतभेद पैदा करने की कोशिश की। सरकारी कामकाज और शिक्षा में हिंदी या स्थानीय भाषाओं की जगह अंग्रेज़ी को प्रोत्साहित किया गया, जिससे आम जनता का संवाद बाधित हुआ और राष्ट्रीय एकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

आज भी दुर्भाग्यवश, कुछ राजनीतिक दल और व्यक्तियों ओछी मानसिकता और व्यक्तिगत लाभ के लिए भाषा के मुद्दे को हवा देते रहते हैं। वे इस प्रकार की बहसों को उभारकर समाज में दरार डालने का प्रयास करते हैं। लेकिन भारत की सांस्कृतिक विरासत और लोगों की समझदारी ने हमेशा इन प्रयासों को नाकाम किया है।

वर्ष 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना सर्वे भवन्तु सुखिन: के भाव से हिंदू समाज को संगठित करने के निहित की गई। भारतीय संस्कृति और संस्कारों का वाहक संघ का स्वयंसेवक उत्तर-दक्षिण ओर पूर्व पश्चिम में प्रांतीय भाषाओं में संवाद के साथ साथ मातृ भाषा का संरक्षक भी बना।द्ध

संघ की शाखाओं ओर बैठकों में संवाद का माध्यम स्थानीय भाषाएं ही रही। यह परंपरा सौ वर्ष बाद यथावत है। संघ ने प्रारंभ से ही भारत की सभी भाषाओं को राष्ट्र की एकात्मक समृद्धि का आधार स्तंभ माना। संघ का स्पष्ट मत है कि भारत की सभी स्थानीय-भाषाएं राष्ट्रीय भाषाएं हैं। कोई भाषा क्षेत्रीय या कमतर नहीं है। राज्यों की भाषाएं सम्मान की पात्र हैं और उन्हें बढ़ावा मिलना चाहिए। बच्चों की शिक्षा की शुरुआत उनकी मातृभाषा या घर की भाषा में होनी चाहिए। इससे समझ बढ़ती है, भाषा-संस्कृति बचती है और बौद्धिक विकास बेहतर होता है। प्रत्येक भारतीय को कम-से-कम तीन भाषाएं आनी चाहिए– मातृभाषा, राज्य की भाषा और एक सम्पर्क भाषा। लोगों को न्याय पाने में भाषा की बाधा नहीं होनी चाहिए। इसलिए अदालतों में, सरकारी आदेशों आदि में स्थानीय भाषाओं का उपयोग बढ़ाया जाना चाहिए।

संस्कृत को भारत की सभ्यता और संस्कृति के मूल को परिभाषित करने वाली भाषा माना जाता है। संस्कृत सभी भारतीय भाषाओं की जननी है। इतना ही नहीं अनेक विदेशी भाषाओं पर भी संस्कृत की छाप दिखाई देती है। संघ ने भाषाओं की जननी संस्कृत को भी उचित स्थान दिया है। संविधान सभा की प्रस्तावना में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी संस्कृत भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने का पक्षधर था, क्योंकि स्वतंत्र भारत के संघर्ष में भाषाई संघर्ष इतना विराट न हो कि भारत की विविधता में एकता का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्कृत भाषा का मूल विलुप्त हो जाए। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को ही मान्यता प्राप्त है जबकि देशभर में 1369 बोलिंया-मातृभाषाएं है।

वर्ष 2023 में भारत ने जब जीद्व20 सम्मेलन की मेज़बानी की, तब उसने विश्व को "वसुधैव कुटुम्बकम" का संदेश दिया। यह वाक्यांश केवल एक नारा नहीं, बल्कि भारत की प्राचीन सभ्यता और समग्र दृष्टिकोण का प्रतीक है। इसमें पूरे विश्व को एक परिवार मानने की भावना निहित है, जो भारतीय संस्कृति की मूल आत्मा है। यह महान विचार संस्कृत भाषा की उसी समृद्ध शब्दावली से उत्पन्न हुआ है, जिसने सदियों से मानवता, एकता और सार्वभौमिक भाईचारे का संदेश दिया है।

भारत के भाव भारतीय भाषा में ही सच्चे प्रतीत होते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत कहते हैं कि संघ के पास भारत की सभी भाषाओं के उत्कृष्ट गीत है इनकी संख्या लगभग 25-30 हज़ार है। संघ विरोधी साने गुरुजी का गीत "बलसागर भारत होवे" को भी संघ ने अपने मूल गीतों में शामिल किया है। वे कहते हैं कि साने संघ विरोधी थे किन्तु सच्चे देशभक्त रहे, इसी आधार पर संघ ने इस गीत को शामिल किया। इसी तरह जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है गीत को सिनेमा में गाया गया है। इसे भी संघ गीतों में शामिल किया गया, क्योंकि इस गीत के पीछे भावना देश प्रेम और समर्पण की रही है।

संघ की अखिल भारतीय बैठकों में देश के दूर-दराज़ क्षेत्रों से आए स्वयंसेवक कन्नड़, पंजाबी, मराठी, तेलुगु, असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और राजस्थानी भाषाओं से जुड़े होते हैं। इन विविध भाषाई पृष्ठभूमियों के बावजूद, इन बैठकों में संवाद का संचालन सदैव हिन्दी में किया जाता है। सभी स्वयंसेवक आपसी समझ और सहयोग से सहज रूप में संवाद स्थापित कर लेते हैं।

यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है, जो भारतीय भाषाओं के बीच एकता, समरसता और पारस्परिक सम्मान का जीवंत उदाहरण है। दक्षिण भारत में संघ कार्यों में संवाद का प्रमुख आधार स्थानीय भाषाएं होती हैं, जिससे न केवल कार्य की सहजता बढ़ती है बल्कि स्थानीय भाषाओं की पहचान और सम्मान भी सुदृढ़ होता है। संघ ने तमिलनाडु में 'देविगा तमिल संगम' नाम से एक संवाद-संबंधी संगठन की स्थापना की है, जो तमिल भाषी समाज से सीधे जुड़कर संवाद और सहयोग का माध्यम बना हुआ है। उत्तर भारत की तरह, दक्षिण भारत में भी संघ के शिविर आयोजित किए जाते हैं, जिनमें विचार-विमर्श, सांस्कृतिक कार्यक्रम और लोकसंपर्क जैसी गतिविधियां होती हैं।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी भारत के उत्कृष्ट विकास में भाषा से जुड़ी बाधाएं बनी रहीं। उस समय भारतीय शिक्षा प्रणाली और शासन-प्रशासन की भाषा में स्थानीय भाषाओं को पर्याप्त स्थान नहीं दिया गया। इसका चिंतन वर्ष 1965 की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में 'भाषा नीति' नामक प्रस्ताव में रखा गया। जिसमें कहा गया कि देश का प्रशासन हमारी अपनी भाषा में चलाया जाए। विदेशी भाषा राष्ट्र की प्रतिभा को अभिव्यक्त नहीं कर सकती न ही उसके विकास में सहायक हो सकती है। इस तरह संघ के इस प्रस्ताव में भारतीय भाषाओं के प्रयोग को प्रखरता से रखा गया।

वर्ष 2018 में नागपुर में आयोजित प्रतिनिधि सभा के प्रस्ताव में "भारतीय भाषाओं का संवर्द्धन एवं संरक्ष" में यह मत रखा गया कि देश में प्रचलित विविध भाषाएं बोलियां हमारी संस्कृति, उदात्त परंपराओं, उत्कृष्ट ज्ञान, विपुल साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के साथ ही वैचारिक नव सृजन हेतु भी परम आवश्यक है। विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध लिखित साहित्य की अपेक्षा कई गुना अधिक ज्ञान गीतों, लोकोक्तियों, लोक कथाओं और लोक परम्पराओं के रूप में होता है। आज भारत की अनेक भाषाएं एवं बोलियां विलुप्त हो चुकी है। कई बोलियों का अस्तित्व संकट में है। संघ की प्रतिनिधि सभा का यह मानना है कि देश की विभिन्न भाषाओं तथा बोलियों के संरक्षण और संवर्द्धन के लिए सरकारों अन्य नीति निर्धारकों और स्वैच्छिक संगठनों सहित समस्त समाज को हर संभव प्रयास करने चाहिए।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संघ की भाषा संरक्षण की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इस नीति में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा को मातृभाषा में प्रदान करने का विकल्प दिया गया है। साथ ही, उच्च शिक्षा और तकनीकी क्षेत्रों में भी हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है। इस पहल से विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता में वृद्धि होगी और शिक्षा का दायरा अधिक सुलभ व सार्थक बनेगा। अब भाषा के भेदभाव के कारण उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों से भारतवासी मुक्त होंगे।

राजकाज से लेकर शैक्षणिक संस्थानों तक मातृभाषा और राष्ट्रभाषा के प्रयोग का प्रचलन संघ के सतत प्रयासों से बढ़ रहा है। डिजिटल तकनीक और एशियाई युग की संवाद-सुविधाओं ने इस दिशा में नई ऊर्जा प्रदान की है। भारतीय भाषाओं के माध्यम से सुगम संवाद और सर्वसमावेशी विकास की दिशा में भारत आगे बढ़ रहा है। इस नवभारत की नींव में संघ का भाषा संरक्षण का समर्पण अतुलनीय है।

–डॉ. निमिषा गौड़,
भाजपा नैत्री, अ. प्रोफेसर
कनोड़िया पी. जी. महिला
महाविद्यालय जयपुर।

माइनिंग सेक्टर प्रोएक्टिव मोड़ पर

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा

राजस्थान का माइनिंग सेक्टर प्रोएक्टिव मोड पर आ गया है। प्रदेश में खनिज से जुड़े सभी पहलूओं के योजनावद्ध क्रियान्वयन, समन्वय, प्रबंधन, प्रभावी मोनेटरिंग, एक्सप्लोरेशन, राजस्व, निवेश एवं रोजगार बढ़ोतरी, सस्टेनेबल माइनिंग, माइनिंग सेक्टर में देश दुनिया में हो रहे नवाचार और नवीनतम तकनीक और उसके प्रदेश में उपयोग सहित विभिन्न बिन्दुओं को लेकर विभाग द्वारा उच्चस्तरीय परियोजना मोनेटरिंग इकाई (पीएमयू) का गठन किया है। माना जा रहा है कि प्रदेश में क्रिटिकल एवं स्ट्रेटेजिक खनिजों के साथ ही प्रधान व अप्रधान खनिजों के विपुल भण्डारों को देखते हुए पीएमयू के गठन से खनिज क्षेत्र को और अधिक गतिशील बनाया जाएगा।

इससे खानें जल्दी परिचालन आने के साथ ही निवेश एवं रोजगार के अवसर बढेंगे। वैसे भी आने वाले समय में माइनिंग सेक्टर की भूमिका में बड़ा बदलाव आने लगा है। अमेरिकी राष्ट्रप्रति ट्रंप की छटपटाहट से इसे आसानी से समझा जा सकता है। अमेरिका कभी कनाडा को अमेरिका का राज्य ही बनाने में जुटा है तो यूक्रेन की खनिज संपदा अपने नाम करवाने या रुस पर दबाव बनाने के पीछे धरती के गर्भ में समाई खनिज संपदा ही है। खनिज संपदा पर आज दुनिया के देशों की नजर है। चीन के वर्चस्व का बड़ा कारण उसका आरईई सहित खनिज संपदा पर एकाधिकार ही है और आज चीन के इस वर्चस्व को कम करने में ही जुटे हुए हैं।

खैर यह विषयांतर होगा पर एक बात साफ है कि माइनिंग सेक्टर में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व व मार्गदर्शन में तेजी से काम होने लगा है और राजथान ऑक्शन सहित रेवेन्यू अर्जन विकास दर आदि में अव्वल हो गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा माइनिंग सेक्टर में विपुल संभावनाओं को देखते हुए राजस्थान के माइनिंग सेक्टर को देश में अग्रणी राज्य बनाने पर जोर देते रहे हैं। नई खनिज नीति, एम-सेण्ड नीति, रिप्स में सहायता प्रावधान, एमनेस्टी योजना सहित प्रक्रिया के सरलीकरण और खनन क्षेत्र विकास के महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं। पीएमयू के गठन के साथ ही खनन क्षेत्र से जुड़ी प्रमुख गतिविधियों को 7 सेक्टरों में चिन्हित किया गया है।

प्रमुख सचिव माइन्स रविकान्त का मानना है कि सभी क्षेत्रों में समन्वित व तेजी से विकास के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को जोड़ते हुए पीएमयू का गठन किया गया है जिससे योजनावद्ध तरीके से तेजी से आगे बढ़ा जा सके। एक्सप्लोरेशन, ऑक्शन, शीघ्र परिचालन, रिसर्च एवं डव्लपमेंट, जीरो लॉस माइनिंग, इकोटूरिज्म की संभावनाओं, पेपरलेस सहित विभिन्न गतिविधियों का समावेश किया गया है। विभाग के वरिष्ठ व विशेषज्ञ अधिकारियों को प्रभारी अधिकारी बनाया गया है। अतिरिक्त निदेशक मुख्यालय महेश माथुर को नोडल अधिकारी व अधीक्षण अभियंता सतर्कता जयपुर प्रताप मीणा को सहप्रभारी बनाया गया है। अतिरिक्त निदेशक भूविज्ञान आलोक जैन, वित्तीय सलाहकार गिरिश कछारा, अधीक्षण खनि अभियंता एनएस शक्तावत, जयगुरुबख्सानी, अधीक्षण भूवैज्ञानिक सुनील वर्मा, संजय सक्सैना आदि को इन दलों की जिम्मेदारी दी गई है।

खनिज क्षेत्र से जुड़े 7 प्रमुख सेक्टरों में से पहले एक्सप्लोरेशन व ऑक्शन का बनाया गया है। इस दल द्वारां कोमोडिटी, मिनरल ग्रेड, खनन के प्रकार सहित विभिन्न बिन्दुओं पर कार्य करेगी। यह दल जीएसआई सहित तकनीकी विशेषज्ञों से समन्वय बनाते हुए एक्सप्लोरेशन से ऑक्शन आदि संबंधित कार्यों को और अधिक प्रभावी गति दी जा सकेगी। इसी तरह से ऑक्शन किये गये माइनर और मिनरल ब्लॉकों को जल्द से जल्द परिचालन में लाने के लिए संबंधित स्टेक होल्डर्स व खान विभाग सहित संबंधित विभागों से समन्वय बनाते हुए आवश्यक अनुमतियां दिलाने में सहयोग के साथ ही शीघ्र परिचालन में लाने का कार्य करेगी। विभाग का जोर खनन क्षेत्र में राजस्व बढ़ाने और राजस्व में किसी भी तरह की छीजत को रोकना भी है और इसके लिए एक दल को मोनेटरिंग सहित आवश्यक सभी जिम्मेदारियां दी गई है।

डीएमएफटी के कार्य को गति देने और राशि के बेहतर उपयोग की मोनेटरिंग की जिम्मेदारी सौंपते हुए डीएमएफटी फण्ड के अन्य प्रदेशों में उपयोग को लेकर अध्ययन सहित योजना, क्रियान्वयन व मोनेटरिंग का फ्रेमवर्क तैयार करने को कहा गया है। राज्य सरकार का सस्टेनेबल माइनिंग पर जोर रहने के साथ ही बदलते परिवेश में यह आवश्यक भी हो गया है। सस्टेनेबल माइनिंग और ऑटोमेशन और तकनीक सेक्टर दल द्वारा स्टार रेंटिंग, बंद व कार्य नहीं कर रही खानों में इको टूरिज्म की संभावनाओं व क्रियान्वयन, डम्प ओवरवर्डन आदि के रिसाइक्लिनिंग व उपयोग, श्रेष्ठ कार्य करने वाली खानों को प्रोत्साहित करने के साथ ही विभागीय सिस्टम को नई तकनीक से जोड़ने और पेपरलेस करने की दिशा में कार्य दिया गया है।

इसी तरह से खनिज क्षेत्र में शोध एवं विकास को बढ़ावा देने, अधिकारियों के रिओरियेंटेशन, खनन क्षेत्र से जुड़े स्टेक होल्डर्स व विभाग के बीच साझा मंच उपलब्ध कराने, देश दुनिया में तकनीक में आ रही बदलाव से रुबरु कराने सहित इस तरह के कार्यों के लिए कॉन्क्लेव, सेमिनार, संगोष्ठियां, प्रशिक्षण कार्यक्रम की रुपरेखा व आयोजन का कार्य किया जाएगा।

राज्य सरकार ने पीएमयू गठित कर जिम्मेदारी तय करने के साथ ही सरकार की ईच्छा शक्ति स्पष्ट कर दी है। अब पीएमयू टीम को जी जान से जुटते हुए माइनिंग के सभी क्षेत्रों में अग्रणी बनाने के लिए जुट जाना होगा।

माइनिंग सेक्टर आज देश दुनिया में महत्वपूर्ण सेक्टर हो गया है। ऐसे में राजस्थान सरकार द्वारा प्रोएक्टिव रोल अपनाने की पहल निश्चित रुप से सराहनीय प्रयास माना जाना चाहिए। आशा की जानी चाहिए कि आने वाले समय में राजस्थान का माइनिंग सेक्टर अग्रणी भूमिका निभाने वाला होगा।

–डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा,
(वरिष्ठ लेखक)

राशिफल बुधवार 8 अक्टूबर, 2025

पंडित अनिल शर्मा

कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष, द्वितीया तिथि, बुधवार, विक्रम संवत 2082, अश्विनी नक्षत्र रात्रि 10:23 तक, हर्षण योग रात्रि 1:33 तक, तैतिल करण सायं 4:08 तक, चन्द्रमा आज मेष राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-कन्या, चन्द्रमा-मेष, मंगल-तुला, बुध-तुला, गुरू-मिथुन, शुक्र-सिंह, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में।

राजयोग रात्रि 10:28 से सूर्योदय तक है। आज अशून्य शयन व्रत है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: लाभ-अमृत सूर्योदय से 9:21 तक, शुभ 10:48 से 12:16 तक, चर 3:10 से 4:38 तक, लाभ 4:38 से सूर्योदय तक।